



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 18117-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के तहत आपराधिक अपील संख्या - 216/2025

रामेश्वर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अजय दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

आपराधिक प्रकीर्ण विलंब माफी आवेदन संख्या 01/2025 पर आदेश

1. यह अपील जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 754/2018 में दिनांक 29.07.2025 को पारित बरी करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जो मामला अपराध संख्या 543/2018, राज्य बनाम बनवारी और अन्य, धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत, पुलिस स्टेशन बह, जिला आगरा में दर्ज है, और इसमें 49 दिनों की देरी हुई है।
2. सूचनादाता-अपीलकर्ता ने तत्काल देरी माफी आवेदन दायर किया है।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता एक गरीब व्यक्ति है और एक चपरासी (निजी) के रूप में काम कर रहा है, जिसका वेतन 5000/- रुपये प्रति माह है। अपीलकर्ता की वित्तीय कठिनाई और बीमारी के कारण, वर्तमान आपराधिक अपील 49 दिनों की देरी से दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उक्त देरी जानबूझकर नहीं की गई है और आग्रह किया गया है कि अपीलकर्ता की वित्तीय पृष्ठभूमि में, वर्तमान अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाए। वर्तमान अपील दायर करने में अपील को देरी माफी आवेदन के साथ शपथपत्र में संतोषजनक ढंग से समझाया गया है और यह जानबूझकर नहीं लगता है, इसलिए, वर्तमान अपील दायर करने में देरी को माफ किया जाता है।

5. कार्यालय अपील को नियमित संख्या आवंटित करेगा।

अपील ज्ञापन पर आदेश

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. इस आपराधिक अपील में चुनौती जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा मामला अपराध संख्या 543/2018 (राज्य बनाम बनवारी और एंटोथर) में धारा 302/34 भा.द.सं.,थाना बाह, जिला आगरा के तहत से उत्पन्न सत्र परीक्षण मामले संख्या 754/2018 में पारित दिनांक 29.07.2025 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आरोपी विरोधी पक्षकार बनवारी और श्रीमती मनीषा को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से अदालत ने बरी कर दिया है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचनादाता-अपीलकर्ता द्वारा थाना बाह में दिनांक 19.10.2018 को एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वह उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कलेक्शन अटेंडेंट के रूप में कार्यरत है। 29.08.2018 को, सूचनादाता-अपीलकर्ता आगरा में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के आवास पर ड्यूटी पर था। वह आमतौर पर लगभग पंद्रह दिनों के बाद घर लौटता है। दिनांक 30.08.2018 को सुबह उन्हें उप जिलाधिकारी के माध्यम से संदेश मिला कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर वह तुरंत आगरा से घर लौटा और अपनी पत्नी का शव लोहे के बिस्तर पर पड़ा पाया। पत्नी के शव के कान और नाक से खून था और उसकी गर्दन पर भी कुछ निशान थे। उसे शक था कि उसकी पत्नी की हत्या की गई है। हालांकि, अपने पड़ोसियों की सलाह पर, उसने पोस्टमार्टम के बिना और थाने में रिपोर्ट दर्ज किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसने धीरे-धीरे यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ था और उसे पता चला कि उस रात उसके पड़ोस में रहने वाले दो लोग, बनवारी और मनीषा उसके घर आए थे। उसे पूरा यकीन है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर उसकी पत्नी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की हत्या की है। बाद में, उन्होंने याद किया कि 29.08.2018 को सुबह लगभग 9:00 बजे, उनकी पत्नी सुनीता ने उन्हें फोन किया था और उन्हें बताया था कि मनीषा ने उन्हें फोन किया था और दो लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा था, क्योंकि वे अपने घर पर रात का खाना खा रहे थे और वे दोनों अपने घर पर रुके थे। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन दो लोगों ने उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

4. सूचनादाता-अपीलकर्ता की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्श क-1 पर, दिनांक 19.10.2018 को मामला अपराध संख्या 543/2018, (स्टेट बनाम बनवारी और अन्य) के तहत आरोपी प्रतिपक्षी संख्या 2 और 3 के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 302/34, थाना बाह, जिला आगरा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और घटना स्थल की नक्सा नजरी तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए।

5. जांच पूरी होने के बाद, आरोपी-विरोधी पक्षकार बनवारी और श्रीमती मनीषा के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, उस पर संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

6. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी-विरोधी पक्षों के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि, आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।

7. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू -1 रामेश्वर (सूचनादाता), पीडब्ल्यू -2 गौरव, पीडब्ल्यू -3 रणवीर सिंह, पीडब्ल्यू -4 कांस्टेबल संजय कुमार, पीडब्ल्यू -5 अजय किशोर (जांच अधिकारी) और पीडब्ल्यू -6 प्रदीप कुमार पांडे (जांच अधिकारी) को शामिल किया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य दिए हैं और 9 अभियोजन पत्र अर्थात्, लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्श क-1 के रूप में, चिक एफआईआर प्रदर्श क -2 के रूप में, जीडी एंट्री प्रदर्श क -3 के रूप में, नक्सा नजरी प्रदर्श क -4 के रूप में, सूचनादाता की आई.डी. प्रदर्श क-5 के रूप में, बनवारी की आईडी प्रदर्श क-6 के रूप में, मनीषा की आईडी प्रदर्श क-7 के रूप में, सी.डी.आर. प्रदर्श क-8 के रूप में और चार्ज-शीट प्रदर्श क-9 के रूप में भी साबित किए हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सभी प्रतिकूल/आपत्तिजनक परिस्थितियों का खुलासा सीआरपीसी की धारा 313 के अधिदेश के अनुसार घटना के उनके संस्करण के लिए प्रश्नोत्तर रूप में अभियुक्त को किया गया था। अभियुक्तों ने उन सभी प्रतिकूल / आपत्तिजनक तथ्यों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।

9. दिनांक 29.07.2025 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, नीचे की अदालत ने भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत आरोपी-विरोधी पक्षों को आरोप से बरी कर दिया है। इस प्रकार, नीचे के न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, वर्तमान अपील को सूचनादाता-अपीलकर्ता द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

10. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान एजीए को भी सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

11. बरी होने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि यदि दो विचार संभव हैं, एक बरी होने का समर्थन करता है और दूसरा दोषसिद्धि का संकेत देता है, तो उच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में, नीचे के न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश को उलट नहीं देना चाहिए। हालांकि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, आरोपी के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसके लिए निर्दोषता की धारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह कानून के एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरे, अभियुक्त ने अपनी बरी कर लेने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को नीचे के न्यायालय द्वारा और मजबूत, पुनः पुष्टि और मजबूत किया जाता है। यह भी देखा गया है कि अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह निष्कर्ष निकाला जाए कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया जा सकने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध एक उचित संदेह से परे साबित हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 10 एससीसी 636 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बरी होने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। एवं आगे यह धारित किया गया है कि यह विकल्प उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध है कि वह नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा प्राप्त सबूतों और निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करे। हालाँकि, यह उन मामलों तक सीमित है जहां नीचे दिए गए न्यायालय का निर्णय विकृत था। शीर्ष न्यायालय ने घोषणा की कि विधिअनुसार "विकृत" शब्द, का अर्थ "सबूतों के भार के विरुद्ध" समझा गया है। यदि दो विचार हैं और नीचे दिए गए न्यायालय ने केवल इसलिए एक विचार लिया है क्योंकि एक और दृष्टिकोण प्रशंसनीय है, तो अपीलीय न्यायालय बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने में उचित नहीं होगा।

13. उपर्युक्त सुस्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं: -

i. सूचनादाता-अपीलकर्ता रामेश्वर को 30.08.2018 को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में जानकारी मिली।

ii लिखित तहरीर (प्रदर्श क-01) के अनुसार, सूचनादाता-अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी का मृत शरीर लोहे के बिस्तर पर पड़ा पाया और मृतक के शरीर के कान और नाक से खून निकलते हुए भी देखा। सूचनादाता-अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुछ निशान भी देखे। लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उसे संदेह था कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, हालांकि, उसने अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम कराए बिना, उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया।

iii सूचनादाता-अपीलकर्ता ने आरोपी बनवारी और मनीषा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 19.10.2018 को संबंधित पुलिस स्टेशन में लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v. एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और इस देरी के संबंध में कोई संतोषजनक कारण और स्पष्टीकरण नहीं है।

iv. सूचनादाता-अपीलकर्ता ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, लेकिन जानबूझकर उचित विचार-विमर्श के बाद इसे दर्ज किया गया था।

vi. हत्या की घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और इसलिए, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

viii. लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) में, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि किसी ने घटना की तारीख को मृतक सुनीता को आरोपी विरोधी पक्षों की संगति में देखा है। उपरोक्त तहरीर में, सूचनादाता-अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसे पता चला था कि आरोपी विरोधी पक्ष बनवारी और मनीषा को घटना की तारीख को उसके घर में देखा गया था, हालांकि, उपरोक्त तहरीर में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जिससे उसे इस तथ्य के बारे में पता चला।

ix. सूचनादाता-अपीलकर्ता रामेश्वर पीडब्ल्यू-1 ने अपने बयान में कहा है कि उसे आरोपी बनवारी के बारे में पता चला था कि वह गौरव पीडब्ल्यू-2 से घटना की तारीख को उसके घर आया था और बाद में उसने उसे आरोपी मनीषा के बारे में टेलीफोन पर सूचित किया था।

x. गौरव पीडब्ल्यू-2 ने अपने बयान में विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि उसने आरोपी को घटना की तारीख को मृतक सुनीता के घर में प्रवेश करते हुए देखा था।

xi. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक सुनीता को अंतिम बार आरोपी विरोधी पक्षों के साथ देखा गया था या किसी ने भी आरोपी विरोधी पक्षकार बनवारी और मनीषा को मृतक सुनीता के घर के अंदर देखा था।

xii. अभियोजन पक्ष मृतक सुनीता की हत्या के पीछे किसी भी मकसद को साबित करने में विफल रहा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

xiii इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मृतक सुनीता की हत्या से संबंधित कोई भी चीज या मृतक सुनीता से संबंधित कोई भी वस्तु आरोपी विपक्षी पक्षों के कब्जे से बरामद की गई हो।

xiv. आरोपी बनवारी के मोबाइल नंबर 9536913599 का सी.डी.आर. प्रस्तुत किया गया था, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए, इसके अभाव में, न्यायालय में पेश किया गया सीडीआर विश्वसनीय नहीं पाया गया था।

xv. मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता घटनास्थल पर पहुंचा था, तब मृतक के कान और नाक से खून नहीं बह रहा था। यदि मृतक के कान और नाक से खून बह रहा होता और गर्दन पर कोई निशान होता, तो शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता के बहनोई जहर सिंह ने उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा होता। जहर सिंह को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, यहां तक कि शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता के भतीजे गौरव (शपथ-2) ने भी अपने बयान में मृतक के कान और नाक से खून निकलने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसलिए, अभियोजन पक्ष मृतक की मृत्यु को हत्या साबित करने में विफल रहा है।

14. उपरोक्त निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आरोपी-विरोधी पक्षों को संदेह का लाभ दिया है और इस प्रकार, उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।

15. विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में सक्षम नहीं है, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आलोक में लिखित रिपोर्ट (तहरीर प्रदर्श क-1) में लगाए गए आरोपों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। हमारे द्वारा जांच करने पर, उक्त निष्कर्षों और उपरोक्त कारणों में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आलोक में, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया गया है, हम ऐसे किसी भी तथ्य पर नहीं आ सके, जिसके आधार पर, आरोप लगाने वाली धाराओं में से किसी भी निष्कर्ष को विकृत या गलत कहा जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी मामले के मूल्यांकन के संबंध में कानून शरद बर्धीचंद सारदा बनाम शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 के मामले के रिपोर्ट के पैराग्राफ 153 से 154 उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट हो गया है। प्रासंगिक हैं और तदनुसार, उन्हें यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"153. इस निर्णय के एक करीबी विश्लेषण से पता चलेगा कि एक आरोपी के खिलाफ एक मामले को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ "सिद्ध होनी ही चाहिए" न कि "हो सकती हैं"। "सिद्ध हो सकती हैं" और "सिद्ध होनी ही चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहबराव बोबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा था, जहां निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं: (एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807)

19. ... निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत को दोषी ठहराने से पहले आरोपी को दोषी होना चाहिए और न केवल दोषी होना चाहिए और "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) उन्हें साबित किए जाने वाले साक्ष्यों को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जाए और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। ये पांच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

17. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सूचनादाता-अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु 30.08.2018 को हुई थी, हालांकि, घटना के संबंध में प्राथमिकी 19.10.2018 को दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने में 50 दिनों का अत्यंत विलंब हुआ था। लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्शक-1 के अवलोकन से पता चलता है कि सूचनादाता ने अपनी पत्नी के शव को लोहे के बिस्तर पर पड़ा देखा। सूचनादाता-अपीलकर्ता ने मृतक के कान, नाक से खून निकलते हुए भी देखा। सूचनादाता-अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के शरीर की गर्दन पर कुछ निशान भी देखे। सूचनादाता-अपीलकर्ता ने अपने स्वयं के लिखित तहरीर में स्वीकार किया है कि उसे संदेह था कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, उपरोक्त तथ्यों को देखने के बावजूद, उसने बिना किसी पोस्टमार्टम के अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और यहां तक कि 30.08.2018 को उसके द्वारा देखे गए किसी भी संदिग्ध तथ्य के बारे में संबंधित पुलिस स्टेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अभियोजन की कहानी में यह एक बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति है।

18. विचारण न्यायालय ने पाया कि सूचनादाता-अपीलकर्ता रामेश्वर पीडब्ल्यू -1 ने अपनी जिरह में कहा है कि जब वह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद बाहर से वापस आया, तो उसके भतीजे गौरव पीडब्ल्यू -2 ने उसे बताया कि उसने 29.08.2018 को आरोपी बनवारी और मनीषा को उसके आवास में प्रवेश करते देखा था। इस गवाह ने आगे कहा कि गौरव पीडब्ल्यू-2 ने उसे 12.10.2018 को इस बारे में सूचित किया। विचारण न्यायालय ने उस तारीख में तीखे विरोधाभास पाए जब उसे 29.08.2018 को गौरव से आरोपी बनवारी और मनीष के घर में प्रवेश करने की सूचना मिली।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. विचारण न्यायालय ने पाया कि एक जगह सूचनादाता ने कहा कि वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद बाह लौट आया और दूसरे स्थान पर, इस गवाह ने कहा कि वह तेरहवी के बाद बाह लौट आया और अंत में कहा कि वह 12.10.2018 को लौटा था। बहस के लिए भी, अगर यह धारित किया जाता है कि सूचनादाता 12.10.2018 को लौटा और गौरव पीडब्लू -2 द्वारा आरोपी बनवारी और मनीषा के बारे में सूचित किया गया था, तो भी एफआईआर दर्ज करने में सात दिनों की देरी हुई है। एफआईआर दर्ज करने में इस देरी के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

20. हमने आक्षेपित निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। सूचनादाता-अपीलकर्ता ने स्वयं अपनी लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) में कई संदिग्ध परिस्थितियों का वर्णन किया है, जो एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, एफआईआर दर्ज करने में लगभग 50 दिनों की अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी हुई है और भले ही, सूचनादाता-अपीलकर्ता के बयान को माना जाए कि उसे आरोपी बनवारी और मनीषा के बारे में केवल 12.10.2018 को जानकारी मिली थी, फिर भी एफआईआर दर्ज करने में सात दिनों की अत्यधिक देरी हुई है। एफआईआर दर्ज करने में इस प्रकार की गई देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। यह अत्यधिक देरी ही अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाती है।

21. सर्वोच्च न्यायालय ने (i) पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 4 एससीसी 578, (ii) पी. राजगोपाल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2019 एससी 2866 (पैराग्राफ 8), (iii) हसमुखलाल डी. वोरा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन 1732, (iv) शेखरन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2024) 2 एससीसी 176 और (v) शिवेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर उर्फ बंटी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 938 में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि एफआईआर विलंब से दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी का कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया गया है, तो ऐसी विलंबित एफआईआर के आधार पर किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना उचित नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियुक्त-विपक्षी पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने में 50 दिनों की अस्पष्ट देरी हुई है। हमारी राय में, एफआईआर दर्ज करने में हुई यह 50 दिनों की अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22. निश्चित रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए तथ्य के गवाहों में से कोई भी हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और इसलिए, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। बेशक, रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो इंगित करता है कि मृतक को अंतिम बार आरोपी की कंपनी में देखा गया था।

23. गौरव पीडब्लू-2 ने अपने बयान में कहा है कि उसने 29.08.2018 को बात करते हुए आरोपी बनवारी और मनीषा को देखा था। इस गवाह ने आगे कहा कि उसने मनीषा और बनवारी को मृतक से मिलने जाते देखा था। हालांकि, पीडब्लू-2 ने विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि उसने आरोपी मनीषा और बनवारी को घटना की तारीख की रात को मृतक के घर में प्रवेश करते हुए देखा था। विचारण न्यायालय ने इस गवाह के बयान के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, पाया कि इस गवाह ने विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि उसने आरोपी बनवारी और मनीषा को घटना की तारीख को मृतक के घर में प्रवेश करते हुए देखा था। इसलिए, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी बनवारी और मनीषा को अंतिम बार या तो मृत सुनीता के साथ देखा गया था या मृतक के घर में प्रवेश किया गया था।

24. हत्या का कथित मकसद यह था कि मृतक को आरोपी बनवारी और मनीषा के बीच अवैध संबंधों के बारे में पता चला और इसीलिए आरोपियों ने मृतक की हत्या की है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि सूचनादाता-अपीलकर्ता रामेश्वर पीडब्ल्यू-1 और गौरव पीडब्लू-2 के बयान के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक सुनीता ने कभी उन्हें आरोपी बनवारी और मनीषा के अवैध संबंधों के बारे में बताया था और वह आरोपी द्वारा उसकी हत्या की आशंका जता रही थी। अभियोजन पक्ष ने आरोपी मनीषा के साथ आरोपी बनवारी के अवैध संबंधों को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने इस बात का भी कोई सबूत नहीं दिया है कि मृतक सुनीता ने कभी कथित अवैध संबंधों का विरोध किया था, जिसके कारण आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी होगी। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में अभियोजन पक्ष कथित मकसद को साबित करने में विफल रहा है।

25. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मृतक सुनीता की हत्या से संबंधित कुछ भी आरोपी के पास से बरामद किया गया था या किसी भी आरोपी की ओर इशारा करने पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बरामद किया गया था। अभियुक्त द्वारा किया गया कथित स्वीकारोक्ति पुलिस के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य है और इसलिए, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

26. वर्तमान मामले में, कोई अंतिम बार देखा गया साक्ष्य नहीं है, हत्या के पीछे कोई मकसद नहीं है और यहां तक कि आरोपी से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हो रही है। अभियोजन पक्ष मृतक की मृत्यु का समय और कारण साबित करने में विफल रहा है। केवल सीडीआर के सबूत बचे हैं। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त बनवारी के मोबाइल नंबर 9536913599 के सीडीआर और आरोपी मनीषा के मोबाइल नंबर 8392830278 और मृतक सुनीता के मोबाइल नंबर 8954480595 को विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत कोई प्रमाण पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था, इसलिए, विचारण न्यायालय ने सही ढंग से यह निष्कर्ष दर्ज किया कि उपरोक्त सीडीआर विश्वसनीय नहीं हैं। अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी यानी "अंतिम बार देखे गए तथ्य" को साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष अन्य महत्वपूर्ण लिंक यानी मकसद, कारण और मृत्यु का समय और किसी भी वसूली को साबित करने में भी विफल रहा है। इस पृष्ठभूमि में एफआईआर दर्ज करने में 50 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन की कहानी के लिए घातक है।

27. सर्वोच्च न्यायालय ने "भास्करराव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य", (2018) 6 एससीसी 591 के मामले में पैराग्राफ संख्या 14,15, और 23 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"14. जैसा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने के बाद, बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यहां कुछ गवाहों के बयानों का पालन करना अनिवार्य कर रहे हैं, जिनका इस मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अपीलीय चरण में सबूतों की सराहना करने की प्रक्रियाओं में, हमें इस अदालत के विचारों को ध्यान में रखना होगा जैसा कि तोता सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, 1987 सीआरआई एलजे 974 में व्यक्त किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं पाया है कि पीडब्लू 2 और पीडब्लू 6 की गवाही को खारिज करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण या तो अनुचित या विकृत थे। उच्च न्यायालय ने जो किया है वह अपने दम पर सबूतों का एक स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करना है और केवल इस आधार पर बरी होने को रद्द करना है कि इस तरह के पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इच्छुक था।

इस न्यायालय ने बार-बार बताया है कि केवल यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों की पुनः मूल्यांकन पर झुका हुआ है, जो नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष से भिन्न है, बरी होने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार नहीं होगा। बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील से निस्तारण में अपीलीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस सीमा से सीमित है कि बरी करने के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मामले में साक्ष्य पर विचार करने के लिए निचली अदालत द्वारा किया गया दृष्टिकोण किसी स्पष्ट अवैधता से दूषित न हो या नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष ऐसा है जिस पर संभवतः नहीं पहुंचा जा सकता था कोई भी अदालत उचित और विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करती है और इसलिए, विकृत के रूप में वर्णित होने के लिए उत्तरदायी है।

जहां मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के मूल्यांकन पर दो विचार संभव हैं और नीचे की अदालत ने एक ऐसा दृष्टिकोण लिया है जो प्रशंसनीय है, अपीलीय न्यायालय कानूनी रूप से बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है यदि यह राय है कि सबूतों पर विचार करने पर नीचे के न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है।

15. रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, 1996 सीआरआईएलजे 2867 के मामले में इस न्यायालय ने कहा:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अलावा किसी अन्य दृष्टिकोण को अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार नहीं बन सकता है जब तक कि यह निष्कर्ष पर न पहुंचे कि विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण व्यवहार में सबूतों के साथ स्पष्ट रूप से अवैध था या इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे। बरी होने पर निर्णय में बैठते समय अपीलीय न्यायालय को सबसे पहले इस सवाल का जवाब मांगने की आवश्यकता होती है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से गलत या स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में देता है, तो बरी करने के आदेश में खलल नहीं डाला जाना चाहिए।

23. इससे पहले कि हम मामले के विश्लेषण के लिए आगे बढ़ें, हमें पहले उस मानक से संबंधित पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय को लागू करना है, जबकि विचारण न्यायालय के बरी करने के आदेश के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करनी है। इस मामले में, विचारण न्यायालय, जिसके बाद पूर्ण सुनवाई होती है, निष्कर्ष पर पहुंचती है और ठोस तर्क से आरोपी को बरी कर देती है। ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय पर अभियुक्त की बेगुनाही की पुष्टि करने के कार्य का और बोझ होता है। ऐसे मामलों में, अपीलीय न्यायालय से बहुत सतर्क रहने की उम्मीद की जाती है और बरी करने के आदेश में इसके हस्तक्षेप की मांग केवल तभी की जाती है जब सम्मोहक कारण और पर्याप्त आधार हों। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के पास उन सबूतों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी किए जाने से अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को और मजबूत किया जा रहा है, उस न्यायालय के निष्कर्ष, जिन्हें गवाहों को देखने और उनके साक्ष्यों को सुनने का लाभ था, केवल बहुत ही ठोस और वास्तविक कारणों से उलट

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया जा सकता है (सूरजपाल सिंह और अन्य बनाम द स्टेट, 1952 सीआरआई एलजे 331)"/

28. उपरोक्त संदर्भित चर्चा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय ठोस कारणों पर आधारित है। हमें निर्णय में कोई विकृति नहीं मिलती है ताकि निचले न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। निचली न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित सराहना का परिणाम है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई गलत तथ्य या चूक नहीं बताई जा सकी। तथ्य का अंतिम न्यायालय होने के नाते, हमने स्वयं यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन किया है कि क्या आक्षेपित निर्णय में कोई विकृति है या नीचे दिए गए न्यायालय ने किसी भी भौतिक साक्ष्य का गलत अर्थ लगाया है। हालांकि, हम रिकॉर्ड से ऐसा कोई तथ्य नहीं जुटा सके ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के वजन के खिलाफ है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप दृष्टिकोण ही संभव है। इसलिए, हमें धारा 413 बीएनएसएस के तहत दायर वर्तमान अपील पर विचार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है, जो परिणामस्वरूप विफल हो जाता है और तदनुसार **खारिज** कर दिया जाता है।

29. वर्तमान आपराधिक अपील को वर्तमान आपराधिक अपील दायर करने में देरी को माफ करने के बाद दाखिल के स्तर में खारिज कर दिया गया है और कार्यालय को पहले से ही इस आपराधिक अपील के लिए नियमित संख्या आवंटित करने का निर्देश दिया गया है, जिसे रिकॉर्ड के उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा।

30. इस न्यायालय के निर्णय को निचली अदालत को प्रमाणित करने के बाद फाइल को रिकॉर्ड के लिए भेज दिया जाए।

जनवरी 27, 2026

मोनिका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।